

delayed because of non-availability of power from the State Electricity Board. The equipment problems faced at Talcher during the commissioning operations have been similar to those at Ramagundam. Besides, Talcher has some problems due to inferior quality of coal. Remedial measures have been taken to overcome these problems more or less on the lines of Ramagundam. As for quality of coal, M/s. Central Collieries Limited, the supplier of coal, have been requested to study the feasibility of beneficiating the coal for upgrading the quality.

(d) and (e). The present feed stock policy gives first preference to the use of indigenously available gas for setting up new fertilizer plants. The policy also envisages use of coal as fertilizer feedstock if the coal based technology is established and viable in the light of the operating experience of the two coal based plants at Ramagundam and Talcher. The question of setting up of new coal based plants can be considered only after adequate experience becomes available from sustained operation of these two coal based fertilizer plants.

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये विश्व बैंक ऋण

240. श्री बागुन सुम्बरई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से अब तक देश में गांवों को बिजली देने और सिंचाई के लिए पम्प सेटों को बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को मिले ऋण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उपर्युक्त निगम और ऋण पाने के लिए विश्व बैंक से वार्ता कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दि. व. महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का वित्त पोषण करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम को विश्व बैंक से दो ऋण प्राप्त हुए हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इस्तेमाल हेतु सामग्री प्राप्त करने के लिए यह ऋण राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा दिया गया है। पहला ऋण (572 आई० एन०) 57 मिलियन अमरीकी डालर का था तथा दूसरा ऋण (911-आई० एन०) 175 मिलियन अमरीकी डालर का था। पहले ऋण का पूर्ण रूप से उपयोग अक्टूबर, 1975-दिसम्बर, 1980 के दौरान कर लिया गया था दूसरा ऋण जो कि अक्टूबर, 1979 से प्रभावी हुआ है, मार्च, 1984 के अन्त तक चलता रहेगा। लगभग 92 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन विश्व बैंक (आई० डी० ए०) को भेजे गये हैं जिसमें से अब तक 85 मिलियन अमरीकी डालर की अदायगी की जा चुकी है।

(ख) जी, हां।

(ग) तीसरे ऋण के लिए इस समय विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच बातचीत चल रही है। तीसरे ऋण के लिए परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक को भेजी जा चुकी है। यह ऋण 1982-83 और 1983-84 के दौरान क्रियान्वित किये जाने वाले ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिये आवश्यक सामग्री की प्राप्ति के लिये होभा।